

'देश में चार जातियां, युवा, महिला, किसान, और गरीब, हमारा बजट इन चारों के लिए है'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि बजट को लेकर सदन में काफी कुछ कहा गया। यह बजट चहुंमुखी विकास करने वाला है। इन लोगों को तकलीफ इस बात से है कि विपक्ष के कुछ विधायकों ने भी खुले मन से तारीफ की। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि देश में चार जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। यह बजट इन चारों को आगे ले जाने वाला है।

मुख्यमंत्री शर्मा कहा कि राजस्थान की नहर परियोजना का नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में इस नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया। कांग्रेस के लोग योजनाओं के नाम बदलने की चर्चा कर रहे थे। अनूपगौरी रसोई का नाम इंदिरा

गांधी के नाम पर कर दिया। अरे भाई, एक परिवार के नाम कितनी योजनाओं के नाम करोगे? मैं अनूपगौरी के नाम से क्या दिक्कत थी। कांग्रेस में एक ही परिवार की भक्ति की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने रॉबर्ट वाड्रा पर भी नाम लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने अभी नेहरूजी का जिक्र किया, उन्होंने आगे भी सबके नाम लिए। वो नाम नहीं लिए होते तो दामादजी का नाम कैसे आता। दामादजी का राजस्थान से क्या रिश्ता है, सब जानते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा- इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रियदर्शिनी था, महिलाओं की योजना का नाम कहां से दूधकर लाए। एक परिवार के प्रति ऐसा समर्पण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान की बात ज्यादा करते हैं,

लेकिन आपातकाल के काले दिनों को भी याद कर लीजिए। इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि किस तरह संविधान की हत्या की गई थी।

संविधान हत्या दिवस का जिक्र करने पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की और कुछ देर के लिए सदन में शोर-शराबा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने केवल थोड़ी घोषणाएं कीं कहते थे कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा। पशुधन स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की, लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं किया। राजसमंद-जालोर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, वहां बने क्या? डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की थी, कितने बने?

मुख्यमंत्री ने कविता कहकर कांग्रेस और डोटासरा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "पेपर लीक इतने हुए, कितने करूँ बखान, पास हुए परिवारजन, क्या-क्या करूँ बयान।

खूब करी मेहमान नवाजी अपनी सरकार बचाने को, जनता का पैसा लुटवाया अपना राज बचाने को। अपने स्वार्थ की खातिर अपनों को ही दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली। पेपर लीक पर सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि अभी छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बड़े मगरमच्छ तो अभी बाहर हैं। वे बिल्कुल चिंता न करें, छोटी मछलियों के लिए इनका जाल छोटा पड़ गया था, लेकिन मैं बूज भूमि से आता हूँ, मेरी सुदर्शन चक्रधारी बंसीवाले में अटूट आस्था है।

'देश में भय का माहौल है, पर, हम भाजपा...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाता है। इक्कीसवीं सदी में एक नये "चक्रव्यूह" की रचना की गई है और वह भी कमल जैसा ही निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री उसके प्रतीक चिह्न को अपने सीने पर टांगते हैं। उस समय जो व्यवहार अभिमन्यु के साथ किया गया था, वही व्यवहार भारत की जनता - युवाओं, किसानों, महिलाओं, छोटे व मध्यम व्यापारियों के साथ किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि "आज भी "चक्रव्यूह" के केन्द्र में छः लोग मौजूद हैं --- ये हैं नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोवल, अंबानी व अडाणी।"

उन्होंने इसको विस्तार से बताते हुए कहा कि वो यह मानते हैं कि आधुनिक "चक्रव्यूह" के पीछे तीन ताकतें हैं।

भारत जिस चक्रव्यूह में फंस चुका है "उसके पीछे तीन ताकतें ये हैं।

1 - पूंजी के एकाधिकार का विचार- सिर्फ दो लोगों को भारत की सम्पूर्ण सम्पदा का स्वामित्व मिलना चाहिए। इसलिए, चक्रव्यूह का एक तत्व वित्तीय शक्तियों के केन्द्रीकरण से निकलकर आ रहा है। दूसरा तत्व देश की संस्थाएं, एजेंसियां, सी.बी.आई., ई.डी. आयकर हैं। तीसरा तत्व है सरकार। गांधी ने कहा, ये तीनों

तत्व "चक्रव्यूह" के केन्द्र में हैं और इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है।"

एम.एस.पी. के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह लम्बे समय से चली आ रही किसानों की मांग है। इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता वादा किया कि एक ऐसा विधेयक लाया जाएगा जो किसानों को उनकी फसल का गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगा।

"मैं देश के किसानों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो (एन.डी.ए.) ने नहीं किया, वो हम किसानों के लिए करेंगे। हम इस सदन में वैधानिक गारंटी वाला एम.एस.पी. (बिल) उनके लिए पारित करेंगे।"

गांधी ने आगे बोलते हुए "इंडिया गठबंधन" के दलों सहित वादा किया कि वे इस सदन में पारित करने के लिए विधेयक गारंटीवाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का (बिल) विधेयक लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना कराने के लिए भी एक विधेयक इस सदन में पारित किया जाएगा, और इस कार्य को इंडिया गठबंधन पूरा करेगा।

उन्होंने सरकार की इस बात को लेकर आलोचना की कि वह युवाओं को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण चिन्ता की उपेक्षा कर रही है, विशेष रूप से बजट में पेपर लीक के मुद्दे पर। उन्होंने उल्लेख किया कि "पेपर लीक" युवाओं

को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है परंतु वित्त मंत्री ने अपने बजट में इसका उल्लेख नहीं किया।"

गांधी ने केन्द्रीय बजट 2024 को "मध्यम वर्ग के लोगों की पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया" और जोर देकर कहा कि इस बजट का एकमात्र उद्देश्य "बड़े व्यवसायियों को मजबूत करना है।"

आगे यह भी कहा कि "इस बजट में टैक्स आतंक के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है, जिसकी मार छोटे कारोबारियों पर बहुत पड़ी है। इसका एकमात्र उद्देश्य बड़े कारोबारियों के एकाधिकार को मजबूती प्रदान करना है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से मध्य वर्ग की पीठ में छुरा भोंका है।"

अध्यक्ष ओम बिड़ला ने चर्चा के दौरान उन लोगों के नामों का उल्लेख किए जाने पर आपत्ति प्रकट की, जो उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे। इस पर गांधी ने जवाब दिया, ठीक है, वे उन लोगों का नाम नहीं बोलेंगे जो सदन में उपस्थित नहीं हैं और इन्होंने अन्य दो लोगों को 'ए-1' व 'ए-2' के रूप में सम्बोधित किया।

राहुल ने कहा कि यह लड़ाई चक्रव्यूह की रचना करने वालों और जो लोग "शिव की बारात" में भरोसा करते हैं उनके बीच है और आगे कहा कि इस "बात" का हिस्सा हर वह व्यक्ति है जो बहु-आस्था एवं विविध पृष्ठभूमि में विश्वास करता है।

देवयानी से जल लेकर जा रहे कांवड़ियों की सांभर थाना पुलिस ने पिटाई की

सांभरझील, 29 जुलाई (निसं)। ग्राम सांभरदा से देवयानी तीर्थ स्थल का पवित्र जल लेकर डीजे की धुन पर नाचते-गाते लौट रहे कांवड़ियों को थाना अधिकारी के निर्देश पर सांभर थाने के पुलिसकर्मियों ने पहले उनका डीजे बंद करवाया व डीजे संचालक के साथ मारपीट की और म्यूजिक सिस्टम जब्त कर कांवड़ियों को थाने ले गईं। बताया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में कांस्टेबल खेमचंद इतना अधिक ड्रेस में भर गया कि थाना परिसर में ही उसने एक कांवड़िया को पकड़कर चांटे मारना शुरू कर दिया। बचाव में जब अन्य कांवड़ियों ने विरोध किया तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कांस्टेबल खेमचंद को थाना परिसर में अंदर ले गए।

इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सनातन प्रेमियों में जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया। घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है।

पुलिस की इस बर्बरता को लेकर सांभर थाना परिसर में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, देवयानी विकास समिति सहित जनप्रतिनिधियों के अलावा, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे थाने पहुंच गईं और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग थी कि तत्काल प्रभाव से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी और थानाधिकारी को सस्पेंड किया जाए।

सुबह से दोपहर तक कई बार वार्ताओं का दौर चला। मामला शांत होते नहीं देख पुलिस ने नजाकत को समझते हुए एस.पी. को भी सूचना दी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी से भी अवगत कराया। पिटाई का वीडियो एडिशनल एस.पी. और जयपुर ग्रामीण एस.पी. तक भी पहुंचा तो उन्होंने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी पुलिसकर्मी के

खिलाफ कार्रवाई किए जाने का संदेश भिजवाया।

धरना स्थल पर मौजूद सभी का कहना था कि जब तक कांस्टेबल को सस्पेंड करने का ऑर्डर उन्हें नहीं दिखाया जाएगा, वे यहां से हिलने वाले नहीं हैं। दोपहर में ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शांतनु कुमार ने कांस्टेबल खेमचंद को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए और सर्वेक्षण की कॉपी धरना स्थल पर मौजूद जनप्रतिनिधियों को भी वॉट्सएप पर उपलब्ध करवाई गई। इसके बाद लोगों ने थानाधिकारी को भी सस्पेंड करने का मुद्दा उठा लिया और यह मामला करीब शाम 5:00 बजे तक चलता रहा।

इसके बाद एडिशनल एस.पी. मौके पर पहुंचे और बात की तथा थानाधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस मामले में पिटाई का शिकार हुए

कांवड़िया ने लिखित में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है।

इस मामले में विधायक विद्याधर चौधरी ने कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कल रात सांभर में कांवड़ियों के साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की घटना हुई है। उसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ।

पूर्व विधायक निर्मल कुमावत का कहना है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है तथा पुलिसकर्मी को निर्लंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

एडिशनल एस.पी. ब्रजमोहन मीणा का कहना है कि शिकायत पर चार सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है तथा अनुसंधान के बाद दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक सारिका खंडेलवाल का कहना है कि मामले की जांच कर सभी दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

'हालांकि, भाजपा ...'

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उन्हें ए-1 तथा ए-2 कहा करेगा। राहुल ने कहा कि इस चक्रव्यूह के खिलाफ शिवजी की बारात है, जिसमें सबका स्वागत है तथा शिवजी को यह बारात (अर्थात इंडिया गठबंधन) इस चक्रव्यूह को तोड़ देगी। इन दिनों, जब राहुल बोलते हैं तो वे रुकते तो हैं ही नहीं, जब वे विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को टक्कर देते हैं, उस समय वे काफी मजेदार बातें भी बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट ने मध्यम वर्ग के सीने तथा पीठ में छुरा भोंका है। उन्होंने कहा कि यही मध्यम वर्ग मोदी सरकार की प्रशंसा के गीत गाते थकता नहीं है। राहुल ने संसद की कार्यवाही की कवरेज करने वाले मीडिया का भी पक्ष लिया, यद्यपि, उनके अनुसार, इनमें से अधिकांश राहुल गांधी को ज्यादा जगह कभी नहीं देते, बल्कि ज्यादातर तो उनकी उपेक्षा ही करते हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि वे उन्हें इस "कांच पिंजरे" से मुक्त कर दें। संसद की सिक्योरिटी द्वारा मीडिया से कहा गया है कि वे लोग मीडिया के लिये बनाये गये ग्लास कंटेनर में ही रहें तथा नये भवन के प्रवेश द्वार पर सांसदों और मन्त्रियों की बाइट्स भी न लें।

उन्होंने कहा कि केन्द्र की नीतियाँ उद्योगों को राज्य से बाहर खदेड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण, देश में एफ.डी.आई. 31 प्रतिशत कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे टैक्स की ज्यादा आय देने वाले राज्यों को आखिर बजट में क्या मिला। उन्होंने

कहा कि अभी हाल ही में हुई नीति आयोग की बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी, का कई विपक्ष-शासित राज्यों ने जो बहिष्कार किया था, उसके लिए केन्द्र सरकार का रुख और तौर-तरीका ही पूरी तरह जिम्मेदार था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर्नाटक सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर चोरी के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बताया कि आरोपी गौतम गर्ग ने करीब 7.48 करोड़ रुपए की कर चोरी की थी। जो एस्टीमेट की धारा 70 के तहत दर्ज बयानों में आरोपी ने माना कि उसने अपने अंकल से मिलकर फर्जी फर्मों को सप्लाई दिखाकर कर चोरी की है। इसके अलावा, विभाग को उसके घर से चार लाख रुपए की नकदी भी मिली थी।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिये यथेष्ट समय नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बिन्दु को मजबूत करते हुए कहा कि विपक्ष शासित राज्य केन्द्र सरकार के सौतेले जैसे व्यवहार से बहुत क्षुब्ध एवं निराश हैं।

निर्देशों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) परीक्षा की प्रक्रिया में स्थिरता नहीं दिला सकता ऐसे में याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।

चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पाथल व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए।

याचिकाओं में कहा गया था कि उन्होंने आर.जे.एस. भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने ओ.एम.आर. शीट में उत्तर देते समय गोलों को सही तरीके से नहीं भरा है।



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

“मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई-बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है।”

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

8 वर्षों की मुख्य उपलब्धियां

62 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त

19.67 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा का वितरण

₹ 1.60 लाख करोड़ से अधिक का बीमा दावा भुगतान



देशव्यापी हेल्पलाइन 14447

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024



e-samridhi



अपनी फसल नाफेड को सीधे बेचने हेतु पोर्टल पर पंजीकरण के लिए QR कोड स्कैन करें

बीमा प्रीमियम के अलावा किसी एजेंट या सीएससी को कोई भी शुल्क न दें।

अतिरिक्त शुल्क मांगने पर 14447 पर सूचना दें।

बीमा भागीदार



अपनी फसलों को आज ही बीमित करने के लिए संपर्क करें

जनसेवा केंद्र

क्रॉप इंश्योरेंस ऐप <https://play.google.com>

पोस्ट ऑफिस

बैंक शाखा

f @PMFBI

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें